

“जो लोग अतीत को याद नहीं करते, वे इसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं”

“फिर कभी नहीं” का वादा, जो होलोकॉस्ट की राख से जन्मा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और वैश्विक नैतिक चेतना का आधार रहा है। फिर भी, जैसा कि जॉर्ज सेंटायाना ने इस निबंध के शीर्षक में चेतावनी दी, अतीत की अत्याचारों और वर्तमान संकटों के बीच समानताएं उन विचारधाराओं और प्रणालीगत विफलताओं में एक परेशान करने वाली निरंतरता को प्रकट करती हैं जो नरसंहार को बढ़ावा देती हैं। यह निबंध तीन अध्यायों के माध्यम से इन समानताओं की पड़ताल करता है: पहला, होलोकॉस्ट में श्रेष्ठता और अमानवीकरण की भूमिका और राष्ट्रसंघ और स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (PCIJ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की इसे रोकने या बंद करने में विफलता; दूसरा, अरबों, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के प्रति इज़राइल के दृष्टिकोण और गाजा में उसकी कार्रवाइयों में आश्वर्यजनक समानताएं; और तीसरा, गाजा में नरसंहार को स्थापित करने वाले आपराधिक इरादे (mens rea) और आपराधिक कृत्य (actus reus) के ठोस सबूत, जो “फिर कभी नहीं” के बाद, नरसंहार कन्वेशन, और संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P) सिद्धांत के तहत राज्यों और अधिकारियों के नैतिक और कानूनी दायित्व को रेखांकित करते हैं।

श्रेष्ठता, अमानवीकरण, और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की विफलता

होलोकॉस्ट, इतिहास के सबसे व्यवस्थित नरसंहारों में से एक, नस्लीय श्रेष्ठता और अमानवीकरण की विचारधारा पर आधारित था, जिसने छह मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों के विनाश को उचित ठहराया। नाज़ी विचारधारा, आर्यन श्रेष्ठता की अवधारणा में निहित, यहूदियों को जर्मन राष्ट्र के लिए एक उपमानव खतरे के रूप में चित्रित करती थी। प्रचार ने यहूदियों को “कीट”, “परजीवी”, और “नस्लीय शत्रु” के रूप में दर्शाया, उनकी मानवता को छीन लिया और उनकी व्यवस्थित विनाश को आसान बनाया। यह अमानवीकरण एक सहज क्रिया नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर रणनीति थी, जैसा कि हिटलर के भाषणों और गोएबल्स के प्रचार में देखा गया, जिसमें यहूदियों को जर्मनी के अस्तित्व के लिए हटाने योग्य एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नाज़ी शासन ने यहूदियों को वारसों जैसे यहूदी बस्तियों में केंद्रित किया, जहां भुखमरी और बीमारी ने हजारों लोगों को मार डाला, फिर उन्हें औशविट्ज़ जैसे नरसंहार शिविरों में निर्वासित किया गया, जहां गैस चैंबरों के माध्यम से औद्योगिक हत्या की गई। यहूदियों को एक समूह के रूप में नष्ट करने का इरादा “अंतिम समाधान” में स्पष्ट था, जो नरसंहार के लिए आपराधिक इरादे को पूरा करता था, जबकि कृत्यों—हत्या, गंभीर नुकसान पहुंचाना, घातक परिस्थितियां थोपना, नसबंदी के माध्यम से जन्म रोकना, और 1.5 मिलियन बच्चों की हत्या—ने बाद में परिभाषित संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेशन (1948) के तहत आपराधिक कृत्य को पूरा किया।

अंतरराष्ट्रीय संस्थान, विशेष रूप से राष्ट्रसंघ और PCIJ, संरचनात्मक कमजोरियों और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण इस नरसंहार को रोकने या बंद करने में विफल रहे। 1920 में शांति बनाए रखने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ में प्रवर्तन तंत्र की कमी थी और यह सर्वसम्मत निर्णयों पर निर्भर था, जिसने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े शक्तियों को नाज़ी जर्मनी के तुष्टिकरण को हस्तक्षेप से ऊपर प्राथमिकता देने की अनुमति दी। राष्ट्रसंघ द्वारा समर्थित एवियन सम्मेलन (1938) यहूदी शरणार्थी संकट को संबोधित करने में विफल रहा, क्योंकि अधिकांश देशों ने शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे नाज़ी अत्याचारों को बढ़ावा मिला। PCIJ, राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग, राज्यों के बीच विवादों को निपटाने में सक्षम था, लेकिन इसके पास होलोकॉस्ट जैसे आंतरिक अत्याचारों को संबोधित करने का कोई जनादेश या शक्ति नहीं थी, जो उस युग में संप्रभुता को मानवाधिकारों से ऊपर प्राथमिकता देने को दर्शाता है। जब होलोकॉस्ट की पूरी तस्वीर सामने आई, तब तक राष्ट्रसंघ निष्क्रिय हो चुका था, और विश्व युद्ध में था, जो कमजोर आबादी की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय तंत्रों की भयावह विफलता को रेखांकित करता है।

इज़राइल के अरबों के प्रति दृष्टिकोण और गाजा में उसकी कार्रवाइयों में समानताएं

इज़राइल का अरबों, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के प्रति दृष्टिकोण और गाजा में उसकी कार्रवाइयां होलोकॉस्ट के साथ भयावह समानताएं प्रकट करती हैं, जो श्रेष्ठता, अमानवीकरण, और व्यवस्थित हिंसा की विचारधाराओं में निहित हैं। इज़राइली नेताओं के ऐतिहासिक बयान फिलिस्तीनियों को बाहर करने या नष्ट करने की दीर्घकालिक मंशा को दर्शते हैं। योसेर वीटज़ (1940 के दशक) ने “अरबों के बिना इज़राइल की भूमि” की मांग की, सभी फिलिस्तीनियों के “हस्तांतरण” की वकालत की, “एक भी गांव, एक भी कबीला” नहीं छोड़ने की बात कही। मेनकेम बेगिन (1982) ने यहूदियों को “मास्टर रेस” के रूप में दावा किया, अन्य नस्लों को “पशु और जानवर, सबसे अच्छे हाल में पशु” के रूप में लेबल किया, जो नाज़ी आर्यन श्रेष्ठता को प्रतिध्वनित करता है। राफेल एइटान (1983) ने फिलिस्तीनियों को “नशीली दवा से भरे कॉकरोच एक बोतल में” के रूप में कल्पना की, जब भूमि पर उपनिवेश स्थापित हो जाए, तो नाज़ी प्रचार के समान उन्हें अमानवीय बनाया। हाल ही में, जेरूसलम फ्लैग मार्च (2023) में हजारों लोगों ने “अरबों को मारो” और “तुम्हारा गांव जल जाए” के नारे लगाए, जबकि 2024 की एक बसने वाली सम्मेलन ने “गाजा में बसने” की योजना बनाई, जिसमें “हमास के बिना”—और निहित रूप से फिलिस्तीनियों के बिना—भविष्य की कल्पना की गई। इसके अतिरिक्त, विरासत मंत्री अमीराई एलियाहु ने नवंबर 2023 में कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध में इज़राइल का एक विकल्प “गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना” हो सकता है, एक टिप्पणी जो, हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अस्वीकृत, विनाश की एक चरम बयानबाजी को दर्शती है जो गाजा के पूर्ण विनाश के लिए कई आह्वानों में प्रतिध्वनित हुई है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या अन्य जगहों पर।

ये दृष्टिकोण गाजा में उन कार्रवाइयों में तब्दील हो जाते हैं जो नाज़ी रणनीतियों को प्रतिबिंबित करती हैं। गाजा, जहां 21 लाख लोग 2007 से नाकाबंदी के तहत 365 वर्ग किलोमीटर में सीमित हैं, एक नाज़ी यहूदी बस्ती जैसा है, जो अब एक “बड़े नरसंहार शिविर” के रूप में परिवर्तित हो गया है। अक्टूबर 2023 से, इज़राइल की मुहिम ने 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसमें 15,000 बच्चे शामिल हैं, बमबारी के माध्यम से, गाजा स्वास्थ्य प्राधिकरणों के अनुसार (2024 के अंत में)। दो महीने की पूर्ण धेराबंदी (मई 2025 तक), जिसे इज़राइल काटज़ (“गाजा में कोई मानवीय सहायता नहीं आने वाली है”) और बेज़ालेल स्मोटरिच (“एक भी गेहूं का दाना नहीं”) ने पुष्ट की, ने अकाल का कारण बना, जिसमें 11 लाख लोग भुखमरी के जोखिम में हैं और बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार (2024)। बुनियादी ढांचे का विनाश—70% आवास, अधिकांश अस्पताल—अजीवनीय परिस्थितियां पैदा करता है, जबकि सफेद फॉस्फोरस का उपयोग जन्मजात विकृतियों से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार (2023)। वेस्ट बैंक में, जिसे इसके चेकपॉइंट और बस्तियों के साथ “यहूदी बस्ती” के रूप में वर्णित किया गया है, 2023 में 83 बच्चे मारे गए, जो पिछले वर्ष की कुल संख्या का दोगुना है, बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों के बीच, यूनिसेफ के अनुसार।

2024 में द टाइम्स ऑफ इज़राइल का एक लेख, जो वेस्ट बैंक में “जीवनक्षेत्र” की मांग करता है ताकि इज़राइल की बढ़ती आबादी (2040 तक 152 लाख) को समायोजित किया जा सके, सीधे नाज़ी प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, जिन्होंने जर्मन बसने वालों के लिए जगह खाली करने के लिए नरसंहार को उचित ठहराया। इज़राइली अधिकारियों के बयान, जैसे योआव गैलेंट के “मानव पशु” (2023) और एक संसदीय दस्तावेज़ जो आईडीएफ से “सफेद झंडा न लहराने वाले सभी को मारने” की मांग करता है (2025), फिलिस्तीनियों को अमानवीय बनाते हैं और अंधाधुंध निशाना बनाते हैं, जैसा कि नाज़ी नीतियों ने यहूदियों को निशाना बनाया। स्मोटरिच का नवंबर 2023 में अतिरिक्त टिप्पणी कि इज़राइल युद्ध के बाद गाजा को नियंत्रित करेगा, एक दीर्घकालिक योजना को सुझाता है जो फिलिस्तीनी उपस्थिति को समाप्त करने के लिए है, जो बसने वाली सम्मेलन की दृष्टि और अरबों के बिना भूमि के ऐतिहासिक आह्वानों के साथ संरेखित है। यह व्यवस्थित हिंसा, गाजा और वेस्ट बैंक में पहले से मौजूद कारावास द्वारा संभव हुई, होलोकॉस्ट के यहूदी बस्तियों और शिविरों के उपयोग को अलग करने और नष्ट करने के लिए प्रतिबिंबित करती है।

गाजा में नरसंहार के सबूत और वैश्विक कार्रवाई का दायित्व

गाजा में सबूत संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेशन और रोम संनियम के तहत नरसंहार के लिए आपराधिक इरादे और आपराधिक कृत्य दोनों को स्थापित करते हैं, जो राज्यों और अधिकारियों को “फिर कभी नहीं” के वादे, नरसंहार कन्वेशन, और R2P सिद्धांत के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं।

आपराधिक इरादा: गाजा में फिलिस्तीनियों को नष्ट करने का इरादा अमानवीय बयानबाजी और स्पष्ट नीतियों के पैटर्न में स्पष्ट है। ऐतिहासिक बयान (वीटज़, बेगिन, इटान) ने बहिष्कार का प्रीडेंट सेट किया, जबकि समकालीन बयान इस इरादे को कार्रवाई में पुष्टि करते हैं: गैलेंट का “मानव पशु”, स्मोटरिच का editor का “एक भी गेहूं का दाना नहीं”, काटज़ का “गाजा में कोई मानवीय सहायता नहीं आने वाली है”, और फ्लैग मार्च का “अरबों को मारो” सभी फिलिस्तीनियों को एक समूह के रूप में नष्ट करने के लिए फ्रेम करते हैं। बसने वाली सम्मेलन का गाजा “हमास के बिना”—और निहित रूप से फिलिस्तीनियों के बिना—योजना कई आह्वानों के साथ संरेखित है जो गाजा के पूर्ण विनाश की मांग करते हैं, जैसे कि 2023 में एलियाहु का सुझाव “गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने” का। स्मोटरिच का दावा कि इज़राइल युद्ध के बाद गाजा को नियंत्रित करेगा, फिलिस्तीनी उपस्थिति को पूरी तरह समाप्त करने की दृष्टि को और संकेत देता है। इज़राइल का 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के उपायों का पालन न करना, जो नरसंहार को रोकने के लिए सहायता पहुंच का आदेश देते थे, इन कृत्यों को इरादे से और जोड़ता है, क्योंकि यह घातक परिस्थितियों को बढ़ाने का एक जानबूझकर विकल्प दिखाता है।

आपराधिक कृत्य: इज़राइल की कार्रवाइयां कई नरसंहार कृत्यों को पूरा करती हैं: (1) **हत्या:** गाजा में 40,000 मौतें, वेस्ट बैंक में 83 बच्चे (2023); (2) **गंभीर नुकसान:** बमबारी, चोटें, आघात, और रसायनों (सफेद फॉस्फोरस) का संपर्क; (3) **जीवन की परिस्थितियां:** धेराबंदी, अकाल, और बुनियादी ढांचे का विनाश, जो अजीवनीय परिस्थितियां पैदा करता है; (4) **जन्म रोकना:** कुपोषण और रसायनों से गर्भपात और प्रजनन क्षति; (5) **बच्चों का हस्तांतरण:** गाजा में 15,000 बच्चों, वेस्ट बैंक में 83 बच्चों की हत्या (“कब्रों में हस्तांतरण”।) फ्लैग मार्च के हमले और वेस्ट बैंक में हिंसा इस पैटर्न को जोड़ते हैं, जो सभी क्षेत्रों में एक व्यवस्थित अभियान दिखाते हैं।

ये सबूत नरसंहार के लिए कानूनी सीमा को पूरा करते हैं, क्योंकि ICJ (2024) ने एक विश्वसनीय जोखिम पाया और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने युद्ध अपराधों के लिए नेतृत्वाहु और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसमें युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी शामिल है। होलोकॉस्ट के साथ समानताएं—श्रेष्ठतावादी विचारधारा, अमानवीकरण, एकाग्रता, और व्यवस्थित हत्या—संकट की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। एलियाहु का परमाणु बम टिप्पणी, भले ही अस्वीकृत हो, एक चरम बयानबाजी को दर्शाता है जो, स्मोटरिच की युद्ध के बाद नियंत्रण की दृष्टि के साथ, पूर्ण विनाश पर विचार करने की इच्छा को सुझाता है, जो नरसंहार के इरादे को और साबित करता है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय संस्थान फिर से विफल हो रहे हैं: संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वीटो द्वारा पंगु है, ICJ के निर्णय लागू नहीं किए जा सकते, और ICC के वारंट में निष्पादन की कमी है, जो होलोकॉस्ट के दौरान राष्ट्रसंघ के विफलताओं को प्रतिबिंबित करता है।

होलोकॉस्ट के सबक से जन्मे “फिर कभी नहीं” के बादे, नरसंहार कन्वेशन (अनुच्छेद I राज्यों को नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए बाध्य करता है), और R2P सिद्धांत (राज्यों को नरसंहार से आबादी की रक्षा करनी चाहिए, विफल होने पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के साथ) के तहत, प्रत्येक राज्य और अधिकारी का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह कार्रवाई करे। इसमें प्रतिबंध लगाना, इज़राइल को सैन्य सहायता रोकना (उदाहरण के लिए, 2023 से अमेरिका के 17 बिलियन डॉलर), ICC वारंट लागू करना, और धेराबंदी और बमबारी को समाप्त करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप का समर्थन करना शामिल है। कार्रवाई न करना राष्ट्रसंघ की गलतियों को दोहराता है, जो मानवता को नरसंहार से बचाने के बादे को धोखा देता है।

निष्कर्ष

होलोकॉस्ट और गाजा उन विचारधाराओं में एक दुखद निरंतरता को प्रकट करते हैं जो नरसंहार को बढ़ावा देती है—श्रेष्ठता और अमानवीकरण—और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की प्रणालीगत विफलताएं जो इसे संभव बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र, ICJ, और ICC, महाशक्तियों की राजनीति और संप्रभुता मानदंडों द्वारा पंगु, गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों को रोकने में विफल रहते हैं, जो श्रेष्ठतावादी बयानबाजी और फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की मंशा के इतिहास द्वारा समर्थित हैं। **आपराधिक इरादे** और **आपराधिक कृत्य** के सबूत, एलियाहु के परमाणु विनाश के सुझाव और स्मोटरिच की युद्ध के बाद नियंत्रण की दृष्टि जैसे चरम बयानों द्वारा और मजबूत किए गए, नरसंहार को निस्संदेह स्थापित करते हैं। “फिर कभी नहीं”, नरसंहार कन्वेशन, और R2P के तहत वैश्विक समुदाय का दायित्व गाजा में अत्याचारों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है, ताकि इतिहास अपने सबसे अंधेरे अध्यायों को न दोहराए। “फिर कभी नहीं” का बादा महज शब्दों से अधिक होना चाहिए—यह न्याय, संरक्षण, और मानवता के लिए कार्रवाई का आह्वान होना चाहिए।